

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	धौलपुर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन (19 दिसंबर, 2025)
2.	दुग्ध उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर
3.	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) : राजस्थान का राज्य पक्षी
4.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. कयाकिंग और कैनोइंग का स्थायी केंद्र 2. जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर की प्रदर्शनी 3. कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी 4. पूरे देश के लिए मॉडल बनी 'RVPNL की पारदर्शी व्यवस्था' 5. राजस्थान का पहला बायोवेस्ट डी-कम्पोज प्लांट : मुहाना मंडी (जयपुर)
5.	रिस्पॉन्ड बास्केट 2025
6.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)
7.	व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA)
8.	लोकसभा में प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025
9.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए नया लोगो
10.	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
11.	गोवा मुक्ति दिवस



राजस्थान परिदृश्य



धौलपुर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन (19 दिसंबर, 2025)



चर्चा में क्यों?

- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 19 दिसंबर, 2025 को धौलपुर के पचगांव में 'राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन' का आयोजन किया गया।



मुख्य बिन्दु:

- इस सम्मेलन का आयोजन राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत किया गया।

--2--

- **आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ** : राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना' के तहत आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ किया गया।
- राजस्थान इस प्रकार की व्यवस्था अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। इसके तहत राजस्थान के मरीज दूसरे राज्यों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ:

शैक्षिक विकास:

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना।

आर्थिक विकास:

- मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना।
- मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना।
- मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क योजना।
- पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना।

सामाजिक कल्याण:

- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना।
- विधवा विवाह उपहार योजना।
- एल.पी.जी. सिलेण्डर सब्सिडी योजना।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।
- किशोरी बालिका योजना।
- महिला विकास कार्यक्रम।

Daily Current Affairs

Date : 20 December, 2025



- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना।
- लाडो प्रोत्साहन योजना।
- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं सुधार) से संरक्षण अधिनियम, 2013
- त्रि-स्तरीय महिला समाधान समिति।
- कालीबाई भील महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान।
- महिला सशक्तीकरण हेतु राज्य हब "मिशन शक्ति"

सामाजिक सुरक्षा:

- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना।
- मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना।
- सम्भाग स्तरीय 'नारी निकेतन' / राज्य स्तरीय 'महिला सदन'।



--:4::--

दुध उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर

चर्चा में क्यों?

- पशुपालन और डेयरी विभाग की 'बेसिक एनीमल हस्बैंडरी स्टैटिस्टिक्स (BAHS) 2025' रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाद सम्पूर्ण देश में दुध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।

पशुपालन और डेयरी विभाग
Department of Animal Husbandry and Dairying

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives World
Department of Animal Husbandry and Dairying, Jaipur, India

INDIA RANKS

1st

in the world in terms of total

MILK PRODUCTION

(SOURCE: FAO)



--:5:--

मुख्य बिन्दु:

- **BAHS- 2025** राष्ट्रीय स्तर पर पशुधन और डेयरी क्षेत्र के रुझानों पर व्यापक आँकड़े प्रदान करता है। हालिया जारी रिपोर्ट 1 मार्च, 2024 से 29 फरवरी, 2025 तक की अवधि के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित है।
 - **दूध उत्पादन** : रिपोर्ट के अनुसार दूध उत्पादन में भारत वैश्विक रैंक में प्रथम स्थान पर है। देश में वर्ष 2024-25 के दौरान कुल दूध उत्पादन 247.87 मिलियन टन होने का अनुमान है।
 - **प्रति व्यक्ति उपलब्धता** : वर्ष 2014-15 में 319 ग्राम/दिन से बढ़कर 2024-25 में 485 ग्राम/दिन हो गई है।
 - **शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य** : उत्तर प्रदेश (15.66 प्रतिशत), राजस्थान (14.82 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (9.12 प्रतिशत), गुजरात (7.78 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (6.71 प्रतिशत)। ये सभी राज्य मिलकर देश के कुल दूध उत्पादन में 54.09 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
- दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयास :**
- **मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना** : प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है। आवेदक एक सक्रिय दुग्ध उत्पादक होना चाहिए जो नियमित रूप से सहकारी समितियों या सरकार द्वारा अधिकृत संग्रह केंद्रों को दूध बेचता हो।
 - **उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड** : 40,000 महिला डेयरी उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम के तकनीकी सहयोग से कोटा, बारां, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर और बूंदी जिलों में ₹41.89 करोड़ की लागत से 'उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड' की स्थापना की गई है।

Daily Current Affairs

Date : 20 December, 2025



- **सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना** : दुग्ध उत्पादकों के लिए सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना के तहत 3 लाख रुपये तक की बीमा राशि दी जा रही है।
- **सरस लाडो मायरा योजना** : जयपुर डेयरी (जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड) द्वारा 05 अप्रैल, 2025 को 'सरस लाडो मायरा योजना' लॉन्च की गई। योजना के अंतर्गत जयपुर डेयरी द्वारा दुग्ध उत्पादकों की बेटियों के विवाह में 21,000 रुपये का मायरा (भात) भरा जाता है।
- **नोट** : राजस्थान में श्वेत क्रान्ति 2.0 के तहत प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 17 जुलाई, 2025 से प्रारम्भ की गई है।
- **राजस्थान की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब** : 11 अगस्त, 2025 को पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने जयपुर जिले के बस्सी में फ्रोजन सीमेन बैंक में स्थापित राजस्थान की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब का उद्घाटन किया।

--7--

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) : राजस्थान का राज्य पक्षी

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने विशेषज्ञ समिति के विस्तृत निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए राजस्थान में 14,013 वर्ग किलोमीटर और गुजरात में 740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB)' के संरक्षण के लिए अंतिम 'प्राथमिकता क्षेत्र' के रूप में नामित किया।

मुख्य बिन्दु:

- न्यायालय ने आदेश दिया कि इस क्षेत्र में कोई भी नया विंड टरबाइन, 2 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले सोलर पार्क या 11 किलोवाट से अधिक की ओवरहेड बिजली लाइनें स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) कम ऊँचाई पर उड़ने वाले पक्षी हैं और उन्हें साफ आसमान में बिजली की हाई-वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देतीं, जिनसे टकराकर वे मर जाते हैं।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) :

- इस पक्षी को वर्ष 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया।
- वैज्ञानिक नाम :** अर्डोटिस निग्रिसेप्स (Ardeotis Nigriceps)
- अन्य नाम :** सोन चिड़िया।
- सर्वाधिक संख्या:** मरू उद्यान (जैसलमेर), सांखलिया (अजमेर) तथा सोरसेन (बारां)
- सुदासरी (जैसलमेर), सोरसेन (बारां) तथा जोधपुर में गोडावण प्रजनन केंद्र स्थित है।
- रामदेवरा (जैसलमेर) में गोडावण का हैचिंग सेंटर (कृत्रिम प्रजनन केंद्र) स्थित है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) भारत में पाई जाने वाली चार बस्टर्ड प्रजातियों में से सबसे बड़ी हैं, अन्य तीन-मैकक्वीन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन हैं।
- GIB का प्राकृतिक आवास मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप था, लेकिन समय के साथ यह घटकर अब केवल राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान तक सीमित रह गया है।
- GIB को उपोष्ण कटिबन्धीय घास के मैदानों की प्रमुख पक्षी प्रजाति माना जाता है।
- भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) की आबादी गिरकर 250 से भी कम रह गई है।

संरक्षण प्रयास:

- भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 : अनुसूची I में।
- CITES : परिशिष्ट I में।
- प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन (CMS) : परिशिष्ट I में।
- IUCN की रेड लिस्ट : गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)
- भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने गोडावण रिकवरी के लिए वर्ष 2015 में, 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम' शुरू किया।
- कार्यक्रम के तहत, भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) और राजस्थान वन विभाग ने संयुक्त रूप से संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किए।

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>कयाकिंग और कैनोइंग का स्थायी केंद्र</p> <ul style="list-style-type: none">राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा उदयपुर को वाटर स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 'फतेहसागर झील' में कयाकिंग और कैनोइंग का स्थायी केंद्र विकसित किया जाएगा।कयाकिंग और कैनोइंग पानी में पैडल मारकर छोटी नाव चलाने के खेल हैं, जिनमें मुख्य अंतर नाव के प्रकार, बैठने की स्थिति और पैडल के डिज़ाइन का होता है।
2.	<p>जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर की प्रदर्शनी</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने नई दिल्ली के द कुंज मॉल में जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर (JCKIC) द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।इस प्रदर्शनी में राजस्थान के प्रमुख हस्तशिल्प, हथकरघा, कारीगरों द्वारा किए गए नवाचार और राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं आजीविका कार्यक्रमों के तहत विकसित डिजाइन-पंजीकृत उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है।
3.	<p>कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज (RUHS) में पहली बार कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की गई।राजस्थान में कॉक्लियर इम्प्लांट उपचार को 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना' के अंतर्गत रखा गया है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को भी यह अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा सुलभ हो सकी है।

4.

पूरे देश के लिए मॉडल बनी 'RVPNL की पारदर्शी व्यवस्था'

- हाल ही में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (RVPNL) द्वारा अपनाई गई पारदर्शी व्यवस्था को अन्य राज्यों के लिए अपनाने के निर्देश जारी किए गए।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (RVPNL) द्वारा राज्य के 400 केवी, 220 केवी एवं 132 केवी ग्रिड उपकेंद्रों पर उपलब्ध अतिरिक्त ट्रांसमिशन क्षमता की अद्यतन जानकारी नियमित रूप से निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक की जा रही है।

5.

राजस्थान का पहला बायोवेस्ट डी-कम्पोज प्लांट : मुहाना मंडी (जयपुर)

- राजस्थान का पहला बायोवेस्ट डी-कम्पोज प्लांट जयपुर की मुहाना मंडी में स्थापित किया जा रहा है, जो जैविक कचरे से CBG (बायो-CNG) गैस और खाद बनाएगा। यह सूरत मॉडल पर आधारित है।
- इस प्लांट में मंडी से प्रतिदिन निकलने वाले 50 टन ग्रीन वेस्ट का उपयोग होगा। यहाँ रोजाना 2000 किलो CBG गैस तैयार की जाएगी।
- इसमें 'बायो मैथेनाइजेशन प्रोसेस' का इस्तेमाल होगा, जिसमें ग्रीन वेस्ट को ऑक्सीजन के साथ 25 दिनों तक डी-कम्पोज किया जाता है।

SERVICES

राष्ट्रीय परिदृश्य

रिस्पॉन्ड बास्केट 2025

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) ने रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 का शुभारंभ किया।



-:12:-

Daily Current Affairs

Date : 20 December, 2025



मुख्य बिन्दु:

रिस्पॉन्ड बास्केट 2025

- यह ISRO के आगामी मिशनों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न प्रमुख विश्वविद्यालयों और अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक एवं अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से अनुसंधान प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण को आमंत्रित करता है।
- यह इसरो की आगामी परियोजनाओं का समर्थन करता है, जिनमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान-4, गगनयान मिशन, शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने वाला यान और मानव द्वारा चंद्रमा पर उतरना शामिल हैं।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:13:--

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, CCI ने बाजार में प्रभुत्व के संभावित दुरुपयोग की जांच के लिए इंडिगो की उड़ानों में आई बाधाओं पर संज्ञान लिया।



Competition Commission of India

मुख्य बिन्दु:

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

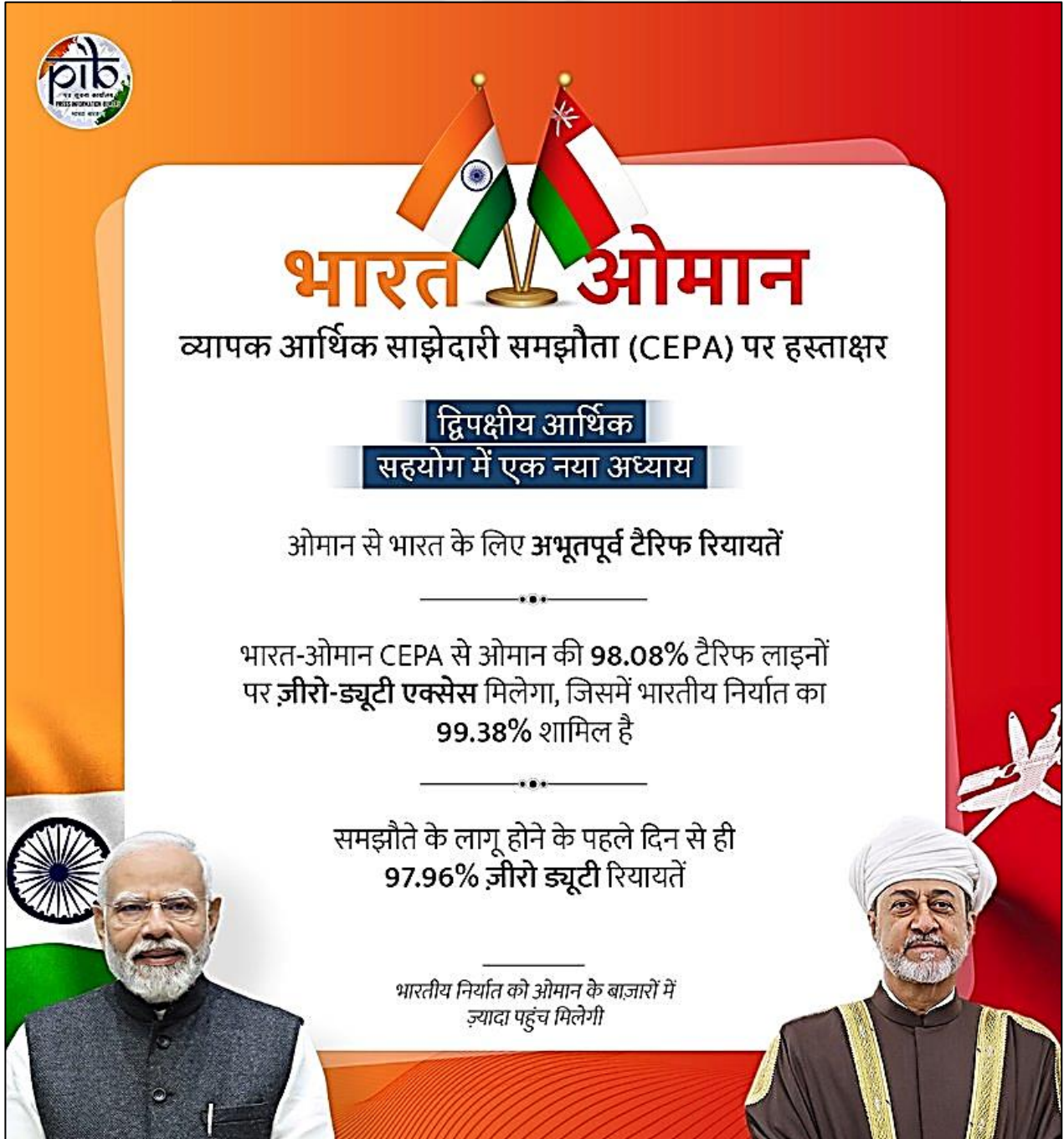
- उत्पत्ति:** प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत एक वैधानिक निकाय।
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा संशोधन किया गया है।
- मंत्रालय:** कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय।
- संरचना:** CCI में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और न्यूनतम 2 व अधिकतम 6 सदस्य।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA)

चर्चा में क्यों?

- भारत और ओमान ने 'व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA)' पर हस्ताक्षर किए।



The infographic features the Indian and Omani flags at the top, with the text 'भारत ओमान' in large red letters. Below this, it states 'व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) पर हस्ताक्षर' and 'द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग में एक नया अध्याय'. It highlights that Oman has agreed to zero tariffs for Indian exports, with 99.38% of goods being zero-tariff. It also mentions that from the day of implementation, 97.96% of Indian exports to Oman's markets will receive zero-duty treatment. At the bottom, there are portraits of Narendra Modi and Sultan Haitham bin Tariq Al Said.

भारत ओमान

व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) पर हस्ताक्षर

द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग में एक नया अध्याय

ओमान से भारत के लिए अभूतपूर्व टैरिफ रियायतें

भारत-ओमान CEPA से ओमान की 98.08% टैरिफ लाइनों पर ज़ीरो-ड्यूटी एक्सेस मिलेगा, जिसमें भारतीय निर्यात का 99.38% शामिल है

समझौते के लागू होने के पहले दिन से ही 97.96% ज़ीरो ड्यूटी रियायतें

भारतीय निर्यात को ओमान के बाजारों में ज़्यादा पहुंच मिलेगी

--:15:--



मुख्य बिन्दु:

- हालिया वर्षों में, भारत ने यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी इसी तरह के मुक्त व्यापार समझौते सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं।

CEPA की मुख्य विशेषताएँ

- **बाजार पहुंच:** वर्तमान के 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए,
- ओमान भारतीय वस्तुओं को लगभग 98% टैरिफ लाइनों (मूल्य के हिसाब से 99.38%) पर शून्य-शुल्क पहुंच प्रदान करेगा।
- भारत ने अपनी लगभग 78% टैरिफ लाइनों पर उदारीकरण की पेशकश की है। इसमें डेयरी, चाय, कॉफी और रबड़ जैसे संवेदनशील उत्पादों को बाहर रखा गया है।
- **सेवाएं और निवेश क्षेत्रक:** ओमान के प्रमुख सेवा क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।
- **पारंपरिक चिकित्सा:** लगभग सभी तरीकों से पारंपरिक चिकित्सा पर पहली बार प्रतिबद्धता जताई गई है। इससे खाड़ी देशों में भारत के आयुष और आरोग्य क्षेत्रों के लिए अवसर उत्पन्न होंगे।
- **भारतीय पेशेवरों के आवागमन में सुगमता:** कुशल पेशेवरों के लिए कोटा बढ़ाना और उनके प्रवेश करने व अस्थायी रूप से ठहरने के नियमों को उदार बनाना शामिल है।
- **गैर-टैरिफ बाधाएं:** यह समझौता व्यापार में आने वाली गैर-टैरिफ बाधाओं को भी दूर करता है।

आर्थिक परिदृश्य

लोकसभा में प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025

- चर्चा में क्यों?**
- केंद्रीय वित्त मंत्री ने लोकसभा में प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 पेश किया।

- मुख्य बिन्दु:**
- विधेयक में निम्नलिखित को समेकित करने का प्रस्ताव है,

- प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एसईबीआई) अधिनियम, 1992
- डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996

मुख्य प्रावधान

- एसईबी की संरचना में सुधार:** एसईबी बोर्ड के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित 9 से बढ़ाकर 15 करने का प्रस्ताव है।
- एसईबीआई बोर्ड के सदस्यों को निर्णय लेने में भाग लेने से पहले अपने किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित का खुलासा करना अनिवार्य है।
- अपराधमुक्ति एवं प्रवर्तन ढांचा:** विधेयक में मामूली, प्रक्रियात्मक और तकनीकी प्रकृति के उल्लंघनों को नागरिक दंड में परिवर्तित करने का भी प्रस्ताव है ताकि व्यापार करने में आसानी और अनुपालन का बोझ कम हो।
- इस विधेयक के तहत "अवैध लाभ या हानि" को नागरिक दंड के दायरे में लाया जाएगा और सजा को केवल इनसाइडर ट्रेडिंग या सामग्री या गैर-सार्वजनिक जानकारी के कब्जे में रहते हुए व्यापार करने जैसे मामलों तक सीमित रखा जाएगा।
- निरीक्षणों पर सीमा:** संहिता के किसी भी नियम या प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, उल्लंघन की तारीख से आठ वर्ष बीत जाने के बाद कोई निरीक्षण नहीं किया जा सकता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए नया लोगो



चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार ने नाबार्ड के सहयोग से "एक आरआरबी, एक लोगो" पहल के तहत सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए एक समान लोगो का अनावरण किया है।



मुख्य बिन्दु:

"वन आरआरबी, वन लोगो" पहल

- भारत में कार्यरत सभी 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक समान दृश्य पहचान लागू करने का एक सुधारात्मक उपाय।
- वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित।



FINANCE & TRUST



LIFE & GROWTH

Daily Current Affairs

Date : 20 December, 2025



आरआरबी के बारे में

- ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण का विस्तार करने और छोटे किसानों, स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों और लघु एवं मध्यम उद्यमों की सेवा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के तहत आरआरबी (आरआरबी) की स्थापना की गई थी।

आरआरबी में त्रिपक्षीय स्वामित्व का ढांचा होता है:

- भारत सरकार - 50%
- संबंधित राज्य सरकार - 15%
- प्रायोजक बैंक - 35%।



-:19:-

एंटी-डंपिंग ड्यूटी

चर्चा में क्यों?

- भारत ने चीन से आयात होने वाले कुछ इस्पात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी आरोपित की है।



मुख्य बिन्दु:

एंटी-डंपिंग ड्यूटी

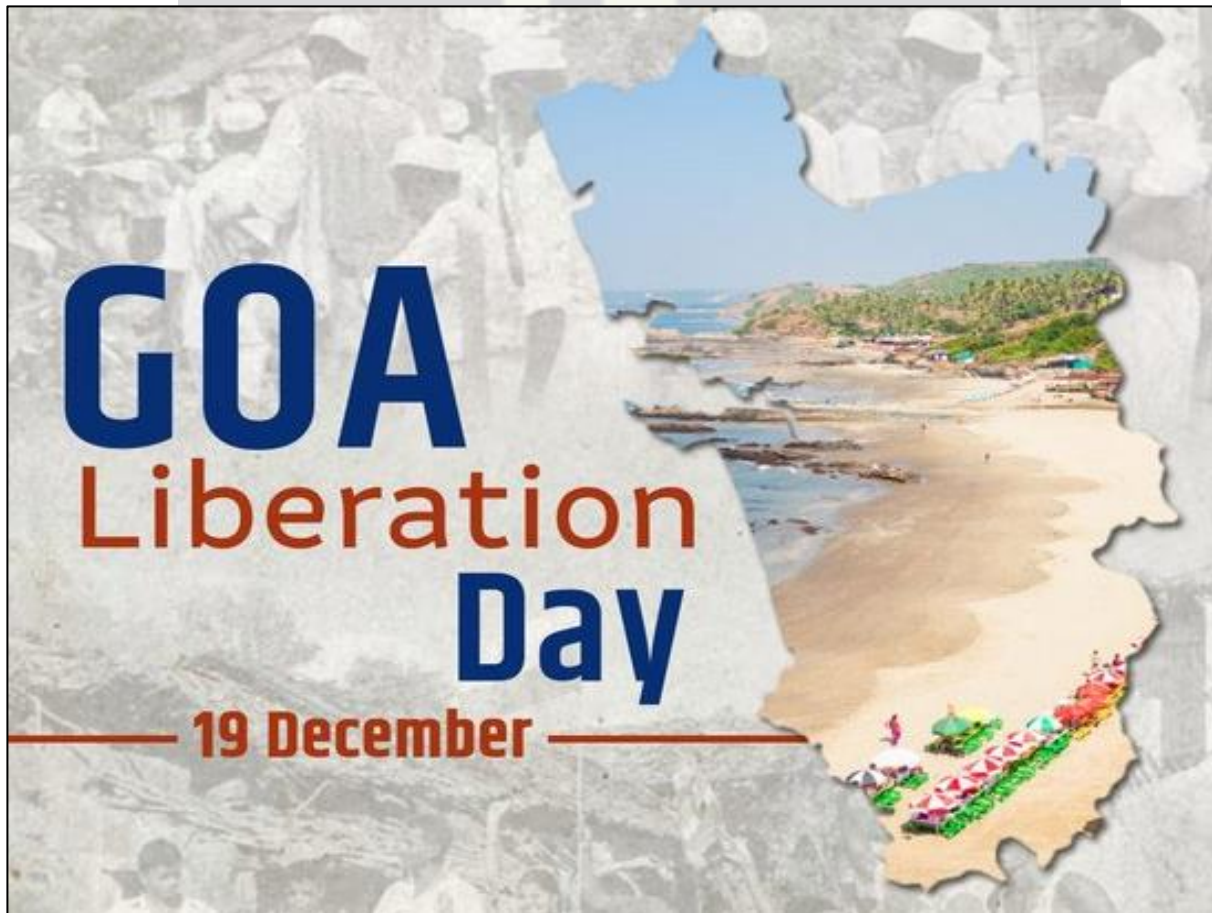
- एंटी-डंपिंग ड्यूटी एक व्यापारिक उपाय है। इसे कोई देश तब लागू करता है, जब कोई देश किसी वस्तु को अपने घरेलू बाजार मूल्य से कम मूल्य पर किसी अन्य देश को निर्यात करता है।
- घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से बचाने के लिए एंटी-डंपिंग प्रशुल्क लगाए जाते हैं।
- निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए WTO एंटी-डंपिंग समझौते के तहत एंटी-डंपिंग उपाय करने की अनुमति दी गई है।

महत्त्वपूर्ण दिवस

गोवा मुक्ति दिवस

चर्चा में क्यों?

- 19 दिसंबर के दिन गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ और 1961 में औपचारिक रूप से भारत में एकीकृत हुआ।



मुख्य बिन्दु:

आक्रमण का क्रम

- वर्ष 1510: अल्बुकर्क ने स्थानीय सरदार तिमोजी की मदद से गोवा पर कब्जा कर लिया।
- मानसून के दौरान आदिल शाह की सेनाओं ने गोवा पर पुनः कब्जा कर लिया।

Daily Current Affairs

Date : 20 December, 2025



- **नवंबर 1510:** अल्बुकर्क अतिरिक्त सैनिकों के साथ लौटा और उसने बीजापुर की सेनाओं को निर्णायक रूप से पराजित किया।

पृष्ठभूमि:

- 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद, शासन को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- भारत सरकार ने पुर्तगाल को गोवा शांतिपूर्वक सौंपने के लिए राजी करने के लिए कई राजनयिक प्रयास किए। पुर्तगाल ने ऐसे सभी अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया। परिणामस्वरूप गोवा मुक्ति आंदोलन का जन्म हुआ।

ऑपरेशन विजय

- जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा गोवा को अपने कब्जे में लेने और उसे शेष भारत में विलय करने के लिए विजय अभियान शुरू किया गया था।
- यह अभियान 36 घंटे से अधिक समय तक चला और इसमें भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा वायु, समुद्र और भूमि पर समन्वित हमले शामिल थे।
- **परिणाम:** पुर्तगाली सेना ने 19 दिसंबर 1961 को आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप दमन और दीव के साथ-साथ गोवा भी मुक्त हो गया।
- 30 मई 1987 को केंद्र शासित प्रदेश का विभाजन हुआ और गोवा को भारत का पच्चीसवां राज्य बनाया गया, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बने रहे।

-:22:-